पुस्तकालय, वाचनालय, चिकित्सा, पठन-पाठन और भोजन की सुविधाएं अपर्याप्त और निम्न-स्तर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के दो आवासीय हाल हैं जिसमें महिलाओं के लिए 8 छात्रावास शामिल हैं । इनमें से एक आवासीय हाल में रसोई की सुविधाओं और महिला कालेज के पुस्तकालय में सुधार की पर्याप्त आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 8वीं योजना अवधि के दौरान आवश्यकता निधियां प्रदान की जाएंगी । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के आठवीं योजना के अपने विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 300 स्थान वाले एक महिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव किया है। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा कालेज द्वारा सभी छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

सुवर्ण रेखा परियोजना के विस्थापितों को बसाया जाना

@@@*179. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुवर्ण रेखा के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विस्थापित लोगों को न तो अभी तक बसाया गया है और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है ;

(ख) क्या मुआवजे की राशि के वितरण में बहुत अनियमितताएं की गई ह,

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से प्रभावित परिवारों को विस्थापित परिवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) क्या विस्थापितों को बसाने के लिए बहुत कम जमीन दी गई है तथा बड़ी संख्या में लोग बिना कोई मुआवजा दिये विस्थापित किये जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी भूमि आदि से संबंधित कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं लाए गए हैं । विस्थापित व्यक्तियों को प्रदान की गयी राहत और पुनर्स्थापन से सम्बन्धित स्थिति दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है (**नीचे देखिए**) सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुन-स्थापन का मार्ग-निर्देश दिसम्बर, 1990 में बिहार सरकार द्वारा प्रतिपादित संशोधित पुनर्वास नीति द्वारा किया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

सुवर्ण रेखा बहु परियोजना परियोजना में राहत और पुनर्स्थापन का ब्यौरा :

क्रम सं०	मद	चंडिल बांध	इचा बांध
1	जलाशय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	17,611	9,763
2.	अर्जित क्षेत्र (हेक्टेयर)	11,465	2,918
3.	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	116	87
4.	गांव जिनमें राहत प्रदान की गयी	86	26
5.	प्रभावित परिवार	9,820	2,218
6.	परियोजना में रोजगार	1,159	277

@@@पूर्वतः तारांकित प्रश्न, 119, 5 मई, 1992 से स्थानांतरित ।

31-1-1992 को सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना के पुर्नस्थापन कार्यक्रम के सोपान-1 के अंतर्गत चंडिल जलमग्न क्षेत्र के 16 गांवों के लिए पुर्नस्थापन सहायता की स्थिति

क्रम सं०	सहायता की मद	परिवारों की संख्या
1.	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	3767
2.	पुनर्वास स्थल पर आवासीय प्लाटों का आवंटन	970
3.	आवासीय प्लाटों के बदले नगद	914
4.	750 रुपए प्रति परिवार की दर से स्थानान्तरण प्रभार	2124
5.	20,000 रुपए प्रति परिवार की दर से पात्र परिवारों को गृह निर्माण अनुदान	526
6.	परियोजना में रोजगार	406 व्यक्ति

टिप्पणी 1-सोपान-1 की पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्रवाई को 30-6-1992 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। बिहार सरकार द्वारा सोपान-II तथा III के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

टिप्पणी 2-इचा बांध का निर्माण अपनी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वर्ष 1995 से पूर्व, बड़ी मात्रा में जल आप्लावन की संभावना नहीं है।

Indira Gandhi Canal Project

*180. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the present stage at which the Indira Gandhi Canal Project in Rajasthan stands;

(b) the additional funds required for its completion;

(c) the likely target for its completion;

(d) the funds likely to be made available by the Central Government during the 8th Five Year Plan and the amount actually provided during the current year;

(e) whether it is proposed to approach the World Bank to seek financial assistance for the canal; and

(f) if so, the amount proposed to be sought and the stage at which this proposal stands at present?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Indira Gandhi Nahar Project is being executed in two stages. Stage-I of the Project has been completed and the design potential of 5.78 lakh hectares has almost been fully utilised. The main canal of Stage-II has also been completed and the work on the distribution system is in hand. The design potential of Stage-II is 8.10 lakh hectares. Against an area of 2.22 lakh hectares opened up through canal construction upto March, 1992 water courses have been constructed in an area of about 1.75 lakh hectares and actual irrigation is 46,600 hectares upto February 1992.

(b) The State Government are yet to finalise the revised estimate for canal and area development works and the lined water courses.

(c) According to the assessment made by the State Government and subject to availability of funds the completion of Stage-II of the project is likely to extend to the 10th Plan.

(d) the eighth Plan has not been finalised. During 1992-93 a provision of Rs. 27.80 crores has been made for Central Assistance under Border Area Development Grant. For area development works the Central Assistance is on a matching basis and it's quantum would depend upon the capacity of the State to provide matching funds as also on the availability of funds.

(e) and (f) The State Government have asked WAPCOS to prepare the feasibility report of the Stage-II of the project for seeking external assistance for the project to complete the remaining works. However, the amount of loan and period for which it is required can be known only after the feasibility report is finalised and the World Bank appraises and accepts the Project.